



भारत में शिक्षक शिक्षा के वर्तमान परिपेक्ष्य पर अध्ययन

डॉ. कंचन जैन, शिक्षाशास्त्र विभाग, सनराइज विश्वविद्यालय

सार

यह रिसर्च पेपर शिक्षक शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य और शिक्षकों की गुणवत्ता की जांच करने का प्रयास करता है। भारत दुनिया में शिक्षक शिक्षा की सबसे बड़ी प्रणालियों में से एक है। विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग और उनसे संबद्ध कॉलेजों के अलावा, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानय निजी और स्व-वित्तपोषित कॉलेज और मुक्त विश्वविद्यालय भी शिक्षक शिक्षा में लगे हुए हैं। किसी राष्ट्र के विकास के चरणों में मानव संसाधन विकास और सशक्तिकरण के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। शिक्षा की आवश्यकता पर, हमारे राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी, जिन्होंने एक बार कहा था कि शिक्षा न केवल नई पीढ़ी को आकार देती है, बल्कि समाज की अपने बारे में और इसे बनाने वाले व्यक्तियों के बारे में मौलिक धारणाओं को प्रतिबिंबित करती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि शिक्षा से ही मनुष्य का निर्माण होता है और राष्ट्र के विकास में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोठारी आयोग की टिप्पणी है— 'भारत का भाग्य उसकी कक्षा में आकार ले रहा है।' लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता काफी हद तक शिक्षकों की गुणवत्ता से निर्धारित होती है। योग्य शिक्षक प्राप्त करने के लिए शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता लाने की आवश्यकता है। न केवल झारखंड में बल्कि अधिकांश राज्यों में शिक्षक शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द : शिक्षक शिक्षा, विश्वविद्यालय ,व्यावसायिक शिक्षा, राष्ट्र निर्माण ।

प्रस्तावना

अधिकांश शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम लगभग समान हैं, फिर भी उनके मानक संस्थानों और विश्वविद्यालयों में भिन्न-भिन्न हैं। शिक्षकों की शिक्षा न केवल सक्षम, प्रतिबद्ध और पेशेवर रूप से योग्य शिक्षकों को तैयार करके स्कूली शिक्षा में सुधार की सुविधा प्रदान करती है जो सिस्टम की मांग को पूरा कर सकते हैं, बल्कि स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के बीच



एक पुल के रूप में भी कार्य करते हैं। शैक्षिक विस्तार, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण, उच्च और व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षा की समग्र गुणवत्ता देश के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। जाहिर है, शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षकों और शिक्षक शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता का प्रत्यक्ष परिणाम है। शिक्षक शिक्षा प्रणाली की संस्थागत प्रभावकारिता में गुणात्मक परिवर्तन लाने का कार्य अपने आप में बहुत बड़ा और चुनौतीपूर्ण है। पिछले दो दशकों में हुए विकास और परिवर्तनों के लिए शिक्षक शिक्षा पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। समग्र प्रगति के लिए शैक्षिक भागीदारी के बेहतर स्तर की आवश्यकता को अच्छी तरह से पहचाना जाता है। कुछ क्षेत्रों में, शिक्षकों की आपूर्ति मांग से कहीं अधिक है, जबकि अन्य में योग्य शिक्षकों की भारी कमी है, जिसके परिणामस्वरूप कम योग्य और अयोग्य व्यक्तियों की नियुक्ति होती है। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के रूप में शिक्षक शिक्षा की भूमिका सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त है। लेकिन भारत में शिक्षक शिक्षा, अपने इतिहास के कारण और इसके नियंत्रण से परे विभिन्न कारणों के कारण, बड़े पैमाने पर केवल स्कूली शिक्षा तक ही सीमित रही है। जाहिर तौर पर शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षकों और शिक्षक शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता का प्रत्यक्ष परिणाम है। शिक्षक शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य और शिक्षकों की गुणवत्ता की जांच करने का प्रयास करता है। भारत दुनिया में शिक्षक शिक्षा की सबसे बड़ी प्रणालियों में से एक है। विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग और उनसे संबद्ध कॉलेजों के अलावा, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानय निजी और स्व-वित्तपोषित कॉलेज और मुक्त विश्वविद्यालय भी शिक्षक शिक्षा में लगे हुए हैं। हालाँकि अधिकांश शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम लगभग समान हैं, फिर भी उनके मानक संस्थानों और विश्वविद्यालयों में भिन्न-भिन्न हैं। शिक्षकों की शिक्षा न केवल सक्षम, प्रतिबद्ध और पेशेवर रूप से योग्य शिक्षकों को तैयार करके स्कूली शिक्षा में सुधार की सुविधा प्रदान करती है जो सिस्टम की मांग को पूरा कर सकते हैं, बल्कि स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के बीच एक पुल के रूप में भी कार्य करते हैं। कुछ क्षेत्रों में, शिक्षकों की आपूर्ति मांग से कहीं अधिक है, जबकि अन्य में योग्य शिक्षकों की भारी कमी है, जिसके परिणामस्वरूप कम योग्य और अयोग्य व्यक्तियों की नियुक्ति होती है। राष्ट्र निर्माण की



प्रक्रिया के रूप में शिक्षक शिक्षा की भूमिका सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त है। लेकिन भारत में शिक्षक शिक्षा, अपने इतिहास के कारण और इसके नियंत्रण से परे विभिन्न कारकों के कारण, बड़े पैमाने पर केवल स्कूली शिक्षा तक ही सीमित रही है।

वर्तमान शिक्षक शिक्षा के परिपेक्ष्य

“शिक्षक बनाये जाते हैं, पैदा नहीं होते” इस धारणा के विपरीत, “शिक्षक पैदा होते हैं, बनाये नहीं जाते”। चूँकि शिक्षण को एक कला और एक विज्ञान माना जाता है, इसलिए शिक्षक को न केवल ज्ञान प्राप्त करना होता है, बल्कि कौशल भी हासिल करना होता है जिसे “व्यापार की तरकीबें” कहा जाता है। “इतिहास की शुरुआत से ही शिक्षा का विकास, विविधता और उसका विस्तार जारी रहा है। प्रत्येक देश अपनी विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान को व्यक्त करने और बढ़ावा देने के साथ-साथ समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी शिक्षा प्रणाली विकसित करता है।” बाद में 1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) 1986 के ये शब्द भारतीय शिक्षा को दिशा देते हैं। नीति में आगे जोर दिया गया है कि “भारत सरकार भी हर पांच साल में समीक्षा करेगीय प्रगति हुई है और आगे के विकास के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश की गई है”। उपरोक्त कथनों के आलोक में, देश में शिक्षक शिक्षा के मानकों के रखरखाव और गुणवत्ता में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई)। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को विभिन्न स्तरों पर शिक्षक शिक्षा को ऐसे विकासों के साथ-साथ भविष्य में गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए उपयुक्त उपाय शुरू करने होंगे। शिक्षक शिक्षा में जनशक्ति नियोजन व्यावहारिक रूप से अनुपस्थित है। शिक्षकों की शिक्षा न केवल सक्षम, प्रतिबद्ध और पेशेवर रूप से योग्य शिक्षकों को तैयार करके स्कूली शिक्षा में सुधार की सुविधा प्रदान करती है जो सिस्टम की मांग को पूरा कर सकते हैं, बल्कि स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के बीच एक पुल के रूप में भी कार्य करते हैं। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के रूप में शिक्षक शिक्षा की भूमिका सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त है। इसका उद्देश्य मानव निर्माण और प्रबुद्ध नागरिक तैयार करना है। लेकिन भारत में शिक्षक शिक्षा, अपने इतिहास के कारण



और इसके नियंत्रण से परे विभिन्न कारकों के कारण, बड़े पैमाने पर केवल स्कूली शिक्षा तक ही सीमित रही है। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों के साथ-साथ सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर बड़े पैमाने पर और दूरगामी विकास और परिवर्तन हुए हैं। इन विकासों ने शिक्षा को प्रभावित किया है, जिसमें भारतीय शिक्षक शिक्षा की समीक्षा और सुधार के लिए शिक्षक शिक्षा का आह्वान भी शामिल है। भारत में शिक्षक शिक्षा का इतिहास बहुत लंबा है। वैदिक काल की गुरुकुल-केंद्रित परंपरा बौद्ध विहार-आधारित प्रणाली के प्रभाव में कुछ हद तक संशोधित और समृद्ध हुई। यह 11वीं शताब्दी ई. तक जारी रहा। इस अवधि के दौरान दोनों परंपराओं में कुछ संशोधन हुए। लिए गए निर्णयों, उपलब्ध कराए गए वित्त और उनके कार्यान्वयन और बाद में मूल्यांकन के ऐतिहासिक रिकॉर्ड अंग्रेजों द्वारा दस्तावेजीकरण के कारण अपेक्षाकृत अधिक व्यवस्थित हो गए। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता हमारे राष्ट्र के इतिहास में एक निर्णायक क्षण है। शिक्षक शिक्षा की सेवा करते हैं, जो मनुष्य निर्माण का एक प्रभावी साधन है। शिक्षक इस कला को सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से सीखते हैं। शिक्षक शिक्षा का एक कमजोर कार्यक्रम इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता। इसका उद्देश्य शिक्षकों की पेशेवर स्थिति को बढ़ाना, उनमें समाज, उनके छात्रों और उनके पेशे के प्रति अधिक प्रतिबद्धता विकसित करना, उनकी पेशेवर दक्षताओं और प्रदर्शन कौशल को बढ़ाना और उन्हें सशक्त बनाना है।

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन

शिक्षा आयोग (1964-66) ने एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसने शिक्षा के सभी चरणों और पहलुओं को कवर करते हुए शिक्षा की एक समान राष्ट्रीय संरचना स्थापित करने के आधार के रूप में कार्य किया। इसमें शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए शिक्षकों की पेशेवर तैयारी की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसने सिफारिश की कि इसके अलगाव को दूर किया जाए और अभ्यास शिक्षण और सेवाकालीन शिक्षा के महत्व पर जोर दिया जाए। इसने शिक्षकों की तैयारी के लिए अधिक धन आवंटित करने, शिक्षकों और उनके शिक्षकों के लिए बेहतर वेतन और बेहतर सेवा शर्तों की सिफारिश की ताकि सक्षम लोगों को पेशे



में आकर्षित किया जा सके। आयोग की सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) तैयार की गई। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के कामकाज की भी समीक्षा की गई। एनसीईआरटी और उसके क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों से शिक्षकों की शिक्षा में बड़ी भूमिका निभाने की अपेक्षा की गई थी।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948) की स्थापना थी, जिसने शिक्षकों की सेवा-पूर्व और सेवाकालीन शिक्षा और शिक्षक तैयारी कार्यक्रम को विश्वविद्यालय प्रणाली से जोड़ने के संबंध में बहुमूल्य सुझाव दिए। इसके बाद, स्कूली शिक्षा की स्थितियों की जांच के लिए नियुक्त माध्यमिक शिक्षा आयोग (1953) ने शिक्षकों की तैयारी के बारे में विशिष्ट सुझाव दिए। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उच्च शिक्षा समिति (1954) और महिला शिक्षा समिति (1959) ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में शिक्षक शिक्षा के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए, लेकिन अपने सीमित दायरे के कारण उन्होंने राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित नहीं किया।

शिक्षा पर समीक्षा समिति (1960) ने शिक्षा और अनुसंधान में स्नातकोत्तर अध्ययन, प्रशासकों की शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षकों की योग्यता के बारे में प्रमुख सिफारिशें कीं। इनमें से अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया और लागू किया गया। केंद्र, राज्य, विश्वविद्यालय और सार्वजनिक एवं निजी उद्यम शिक्षक शिक्षा की देखभाल करते थे। साथ ही इसकी समस्याओं की समग्रता से जांच नहीं की गयी। अध्यापक शिक्षा के लिए संसाधनों की उपलब्धता भी एक समस्या थी। इसके अलावा, शिक्षा के एजेंडे में शिक्षक शिक्षा को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया।

गैर-वैधानिक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की स्थापना 1974 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी और यह एनसीईआरटी में स्थित थी। इसके परिणामस्वरूप, कई विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों ने शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को संशोधित किया।

राष्ट्रीय शिक्षक आयोग (1983) ने शिक्षक शिक्षा की समस्याओं और समाज में शिक्षकों की स्थिति का गहराई से अध्ययन किया। एनपीई (1986) के बाद एक्शन प्रोग्राम (1986) आया, जिसमें नीति को कार्रवाई में बदलने के आवश्यक विवरण दिए गए। इसका जोर



सेवाकालीन और सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों, कंप्यूटर शिक्षा और शिक्षक तैयारी के नए और वैकल्पिक मॉडल दोनों के संवर्धन पर था। यह जानकर खुशी होती है कि एनपीई (1986) में दिए गए निर्देशों और कार्रवाई कार्यक्रम की सिफारिशों को बड़े पैमाने पर उत्साहजनक परिणामों के साथ लागू किया गया था। दूरगामी शैक्षिक और सांस्कृतिक परिणामों के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नए विकास, उत्तर आधुनिकता, प्रति-संस्कृति, मूल्य संकट और उत्तर-औद्योगिक समाज की चुनौतियाँ स्पष्ट हो गईं।

शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम

पिछली आधी सदी में और विशेष रूप से, हाल के दशकों में, शिक्षण-अधिगम में भारी बदलाव आ रहे हैं। छात्र-केंद्रित कक्षाओं की ओर बदलाव आया है, जिसमें शिक्षक की भूमिका एक निरंकुश मास्टर के बजाय सीखने के सुविधा प्रदाता के रूप में अधिक है। अतीत के विपरीत जब शिक्षक को पाठ्यक्रम की सामग्री को छात्रों के निष्क्रिय दर्शकों तक स्थानांतरित करने का काम सौंपा जाता था, आज कक्षा में नए प्रयोग किए जा रहे हैं जिनमें परियोजना आधारित शिक्षा, सोच कौशल का विकास और खोज सीखने के दृष्टिकोण शामिल हैं। कई शिक्षकों को नए पाठ्यक्रम के पीछे की अवधारणाओं को लागू करने के लिए ठीक से प्रशिक्षित नहीं किया गया है और कई लोग पाठ्यक्रम को ठीक से लागू करने के लिए सुसज्जित नहीं हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षक शिक्षा केंद्रों और शिक्षक शिक्षा में अपनाए जाने वाले पाठ्यक्रम में शिक्षा के नए रुझानों पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। पिछले दो दशकों के दौरान, शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम की कड़ी आलोचना हुई है और उनकी कमजोरियाँ अच्छी तरह से उजागर हुई हैं। इस बात पर जोर देना होगा कि शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की अवधि बढ़ाए बिना इन लक्ष्यों को हासिल नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के आने और इन संस्थानों के लिए अनिवार्य मानदंडों और मानकों पर जोर देने तक लाभ के उद्देश्य से पूरे राज्य में शिक्षक शिक्षा संस्थान तेजी से फैल रहे हैं। उनके हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप, कई संस्थानों ने कक्षाओं के साथ भवनों का निर्माण किया है और अपने मानकों को पूरा करने के लिए



बुनियादी ढांचे की खरीद की है। इन संस्थानों को शिक्षक प्रशिक्षकों के वेतन को सरकारी वेतनमान में मूल राशि तक बढ़ाने के लिए भी मजबूर किया गया था। शैक्षणिक और व्यावसायिक कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हैं। पुराने शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम के कारण प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रदर्शन में शायद ही कोई अंतर है। शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम को चिकित्सा विज्ञान के पाठ्यक्रम की तरह एक समग्र रूप में एकीकृत और मिश्रित करना होगा। इस प्रकार, शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम का पुनर्निर्माण समय की एक महती आवश्यकता बन गया है। इसे सूचना आधारित से अनुभव आधारित में बदलना होगा। यहां तक कि जब समय-समय पर वेतन संशोधन से स्थायी कर्मचारियों का वेतन आसमान छू जाता है, तब भी उनके समकक्ष बी.एड. केंद्र केवल अल्प वृद्धि का सपना देख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि निजी संस्थानों की शक्तिशाली लॉबी शिक्षक प्रशिक्षकों को उचित सौदा प्रदान करने में विश्वविद्यालयों की अनिच्छा को प्रभावित करती है। ऐसा लगता है कि एनसीटीई, अतीत के विपरीत, चुप है और अलग-थलग है और ऐसा ही माननीय भी करते हैं। शिक्षा मंत्री. निजी शिक्षा संस्थान के मालिकों को कोई नाराज नहीं करना चाहता। यह स्वयं शिक्षक शिक्षा समुदायों को अलग-थलग करने के लिए लाभ उन्मुख प्रबंधन के लिए पर्याप्त गुंजाइश प्रदान करता है। शिक्षक शिक्षा संस्थानों में प्रशिक्षु शिक्षकों का मूल्यांकन एक और बड़ा मजाक है। उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों और कम उपलब्धि हासिल करने वालों के बीच अंकों में अंतर न्यूनतम है और संकाय सदस्यों को या तो प्रशिक्षुओं को उच्च अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने या कम अंकों के साथ आलसी को दंडित करने में कम से कम परवाह है। इस प्रकार, इन संस्थानों में प्रवेश करने वाले अधिकांश प्रशिक्षु अच्छे अंकों के साथ बाहर आते हैं।

भारत में शिक्षक शिक्षा के लाभ

शिक्षा जगत में सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षकों को भी बदलते परिवेश के साथ खुद को नवाचार और नवीन ज्ञान की जानकारी रखना अतिआवश्यक है। दूरस्थ शिक्षण पाठ्यक्रमों में भी, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षक को बेहतर शिक्षण परिणामों के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल संचार उपकरणों का उपयोग



करने में मदद करता है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षकों के लिए उनकी दक्षता, क्षमता, ज्ञान, व्यावसायिकता उनके काम के लिए प्रेरणा में सुधार करने में सहायक है। शैक्षणिक ज्ञान के साथ-साथ कौशल और नैतिकता की भी आवश्यकता है। इसलिए, शिक्षक केवल किताबें पढ़ाने तक ही सीमित नहीं हैं।

निष्कर्ष

बी.एड की प्रवेश प्रक्रियाएँ पूर्णतः व्यवस्थित किया जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य के शिक्षा विभाग में एक नियोजन इकाई होनी चाहिए। इस इकाई का कार्य स्कूलों के विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों की मांग और आपूर्ति को विनियमित करना होना चाहिए। अभ्यास करने वाले स्कूलों को विश्वास में लेना होगा। इसके लिए शिक्षक महाविद्यालयों के स्टाफ के सदस्यों को विद्यालयों के साथ घनिष्ठ रूप से जोड़ा जाना चाहिए। शिक्षक शिक्षा में पत्राचार पाठ्यक्रम प्रदान किया जाना चाहिए, जिसमें प्रवेश के लिए सख्त और उच्च स्क्रीन और मूल्यांकन का सटीक तरीका होना चाहिए। समग्र प्रगति के लिए शैक्षिक भागीदारी के बेहतर स्तर की आवश्यकता को अच्छी तरह से पहचाना जाता है। इसे साकार करने में शैक्षणिक संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा की प्रकृति और कार्य को बदलने के लिए की गई विभिन्न पहलों में परिलक्षित होती है – औपचारिक और गैर-औपचारिक दोनों। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच को विकास के लिए आवश्यक माना जाता है। इससे शिक्षक शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता हो गई है ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक तैयार किए जा सकें। हाल के दशकों में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त विभिन्न आयोगों और समितियों ने शैक्षिक प्रणाली की आवश्यकताओं के अनुकूल गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया है। पिछले वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संदर्भों में तेजी से बदलाव के कारण नए जोर सामने आए हैं। प्रणाली अभी भी ऐसे शिक्षकों को तैयार करती है जो प्रारंभिक शिक्षक तैयारी कार्यक्रमों के पूरा होने पर आवश्यक रूप से पेशेवर रूप से सक्षम और प्रतिबद्ध नहीं होते हैं। सिद्धांत और व्यवहार दोनों में अध्ययन के पाठ्यक्रमों को पुनर्गठित किया जाना चाहिए। इसलिए एक शिक्षक शिक्षा विभाग को चाहिए विशेष नवोन्मेषी



कार्यक्रम अर्थात् सेमिनार, सेमिनार का संयोजन, व्याख्यान के साथ चर्चा, टीम शिक्षण और पैनल चर्चा आयोजित करना। बड़ी संख्या में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान जो उपदेश देते हैं उसका अभ्यास नहीं करते हैं। अर्जित किए गए कई कौशल और सीखी गई पद्धतियों का वास्तविक स्कूल प्रणाली में शायद ही कभी अभ्यास किया जाता है। यह पाठ्यक्रम में यथार्थवाद और गतिशीलता लाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

सन्दर्भित ग्रन्थ

- ईटन, एसईय ड्रेस्लर, आर.य गोरेलुक, डी.य बेकर, एस. (2015)। “मिश्रित और ई-लर्निंग मॉडल पर ध्यान देने के साथ ग्रामीण और दूरस्थ सेवा-पूर्व शिक्षक तैयारी पर साहित्य की समीक्षा”। वर्कलुंड स्कूल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड पब्लिकेशन । डीओआई : 10.5072/घप्रिज्मध31625 ।
- पश्चिम, ई.य जोन्स, पी. (2007). “ग्रामीण समुदायों की सेवा करने वाले शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में प्रयुक्त योजना प्रौद्योगिकी के लिए एक रूपरेखा”। ग्रामीण विशेष शिक्षा त्रैमासिक । 26 (4): 3–15. डीओआई : 10.1177/875687050702600402 । एस2सीआईडी 142315421 ।
- ‘ वीटजेनकैंप, डीजेय होवे, एमईय स्टेकेलबर्ग, एएलय रैंडविल्फ, आर. (2003). “लक्ष्य मॉडल: ग्रामीण शिक्षक तैयारी संस्थान शैक्षिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से पीडीएस के आदर्शों को पूरा करते हैं” । प्रौद्योगिकी और शिक्षक शिक्षा में समसामयिक मुद्दे । 2 (4).
- ‘ विनस्टेड फ्राई, एस. (2006). “ग्रामीण छात्र शिक्षकों के लिए एक प्रौद्योगिकी समर्थित प्रेरण नेटवर्क” (पीडीएफ) ।
- ‘ “एसडीजी4 के 10 लक्ष्य” । शिक्षा के लिए वैश्विक अभियान . 2020-09-22 को लिया गया ।
- ‘ रोसेर-कॉक्स, मिशेल (2011)। शिक्षकों को तैयार करने में सांस्कृतिक जवाबदेही और प्रेरणा: पूर्व-सेवा शिक्षक: क्या सांस्कृतिक जवाबदेही विशिष्ट सेटिंग्स में पढ़ाने



के लिए प्रत्याशित आत्मनिर्णय को प्रभावित करती है? . लैंबर्ट अकादमिक प्रकाशन ।
पी। 172. आईएसबीएन 978–3844384697.

- ' रोसेर और मैसी (2013)। शैक्षिक नेतृत्व: स्वयं की शक्ति । पीटर लैंग.
- ' रिचर्ड, इंगरसोलय एम, स्मिथ, थॉमस (1 जनवरी 2004)। "क्या अध्यापक की प्रेरणा और सलाह सेफार्क पड़ता है?" . जीएसई संकाय अनुसंधान ।
- ' वोंग, हैरी के. (2004). "प्रेरण कार्यक्रम जो नए शिक्षकों को पढ़ाते और सुधारते रहते हैं"। छौट बुलेटिन । 88 (638): 41–58. डीओआई : 10.1177/019263650408863804 । एस2सीआईडी 144066549
- गिब्सन, आईडब्ल्यू (1994)। "ग्रामीण शिक्षण के लिए शिक्षकों की व्यावसायिक तैयारी में नीति, अभ्यास और आवश्यकता" (पीडीएफ) । ग्रामीण शिक्षा में अनुसंधान जर्नल । 10 (1): 68–77.
- "ए लर्निंग अल्बर्टा: ग्रामीण अल्बर्टा में उन्नत शिक्षा: चुनौतियाँ और अवसर: एक चर्चा दस्तावेज" (पीडीएफ) । एडमॉन्टन: अलबर्टा एडवांस्ड एजुकेशन। 2005.
- "ग्रामीण और दूरस्थ शिक्षा रिपोर्ट" (पीडीएफ) । उत्तरी अल्बर्टा विकास परिषद। 2010.
- ईटन, एसईय गेरेलुक, डी.य ड्रेस्लर, आर.य बेकर, एस. (2017)। "एक कनाडाई ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा शिक्षक तैयारी कार्यक्रम: पाठ्यक्रम डिजाइन, छात्र सहायता और सहभागिता"। अमेरिकन एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन (एईआरए) के वार्षिक सम्मेलन, सैन एंटोनियो, टीएक्स, यूएसए में प्रस्तुत किया गया पेपर । डीओआई : 10.5072/प्रिज्म/31627 ।